



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2009/पौष 16, 1930

No. 5]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2009/PAUSA 16, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2009

सं. 126 (आर ई-2008)/2004—2009

फा. सं. 01/36/218/56/एम 09/नीति-5/ईपीसीजी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, (आर ई-2008) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

2. प्रथम दो वर्षों के लिए निर्यात दायित्व में वृद्धि प्रदान करने से संबंधित पैराग्राफ 5.11 में दिए गए प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

“पूरा न किए गए निर्यात दायित्व पर आनुपातिक रूप से बचाए गए शुल्क के 2 % के बराबर संयोजन शुल्क के भुगतान पर की निर्यात दायित्व अवधि को पहली बार बढ़ाने अथवा प्राधिकार पत्र के तहत लगाए गए कुल निर्यात दायित्व के 10% तक लगाए गए निर्यात दायित्व को बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, निर्यातक के विकल्प पर, मांगे गए प्रत्येक वर्ष के विस्तार हेतु अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। निर्यात दायित्व अवधि में ऐसे पहले विस्तार की अवधि अधिकतम दो वर्ष हो सकती है।”

3. पैरा 5.11 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th January, 2009

No. 126 (RE-2008)/2004—2009

F. No. 01/36/218/56/AM 09/Pol. -V/EPCG. I.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. I) (RE-2008).

2. The provisions related to grant of extension in export obligation for the first two years given in paragraph 5.11 are amended to read as under :

“Concerned Regional Authority may consider request for grant of first extension in E.O. period on payment of composition fee equal to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled export obligation or an enhancement in export obligation imposed to the extent of 10% of total export obligation imposed under authorization, as the case may be at the choice of exporter, for each year of extension sought. Such first extension in E.O. period can be for a maximum period of two years.”

3. All other provisions of Para 5.11 remain unchanged.

4. This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.